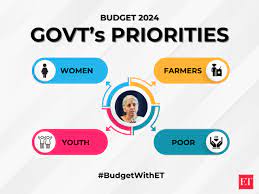
Name:-Pranali Shivale

Topic-Budget 2024

Budget 2024



1. समावेशी विकास और वृद्धि:सरकार का विकास दृष्टिकोण समावेशी है और समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। यह सभी के लिए आवास, सभी के लिए ईंधन गैस और सभी के लिए बैंक खाते जैसे कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है। सरकार ने व्यवस्थित असमानताओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे कि व्यय के बजाय परिणामों पर ध्यान देकर।
2. गरीबों को सशक्त बनाना: सरकार गरीबों को सशक्त बनाने में विश्वास करती है, और हक़-आधारित कार्यक्रमों के पहले के दृष्टिकोण से हट गई है। यह पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में स्पष्ट है, जो किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार ने गरीबों के लिए ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे कि पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से।
3. युवाओं को लैस और सशक्त बनाना: सरकार का यह मानना कि देश की समृद्धि युवाओं को लैस और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो युवा पीढ़ी के विकास और सशक्तिकरण को केंद्र में रखता है। इस दृष्टिकोण के तहत, दो प्रमुख पहलों का उल्लेख किया गया है: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्किल इंडिया योजना।
4. समग्र शिक्षा: NEP 2020 समग्र शिक्षा पर जोर देती है, जिसमें विद्यार्थियों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान, क्रिटिकल थिंकिंग, और जीवन कौशल सिखाया जाए। शिक्षा के नए ढांचे को 5+3+3+4 प्रणाली में विभाजित किया गया है, जो पूर्व-प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा को व्यापक बनाता है|
5. फ्लेक्सिबिलिटी: छात्रों को विषयों का चयन करने में अधिक लचीलापन देना, जिससे वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकें। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, जिससे दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। देश भर में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां युवाओं को विशिष्ट कौशल सिखाए जाते हैं।
6. उद्योग-संबंधित कौशल: युवाओं को उन कौशलों का प्रशिक्षण देना जो उद्योग और बाजार की मांग के अनुकूल हों। युवाओं को न केवल नौकरी पाने के लिए तैयार करना बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करना।ये पहल युवा पीढ़ी को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने और उन्हें समाज और अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं|
7. अर्थव्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करना:अर्थव्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करना:सरकार उच्च विकास के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुधारों, निवेशों और घरेलू मांग को बढ़ावा देने वाली पहलों के संयोजन के माध्यम से हासिल किया जाएगा। सरकार राजकोषीय समेकन और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
8. सुधार:सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रखेगी। इसमें कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देना, श्रम बाजार सुधार और भूमि अधिग्रहण सुधार शामिल हैं।सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगी।सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास करेगी।
9. निवेश:सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाएगी। इसमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह शामिल हैं।सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी।सरकार सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी।
10. घरेलू मांग को बढ़ावा देना:सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी।सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगी।सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रयास करेगी।सरकार राजस्व व्यय को कम करेगी।सरकार राजस्व संग्रह को बढ़ाएगी।
11. यह सब कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करेगा:सुधारों से कारोबार करने में आसानी होगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।निवेश से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, ऊर्जा क्षेत्र में विकास होगा और सामाजिक क्षेत्र में विकास होगा। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।घरेलू मांग को बढ़ावा देने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उपभोग बढ़ेगा। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।राजकोषीय समेकन से सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बढ़ेगी।
12. कर प्रस्ताव: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं:सरकार ने प्रत्यक्ष (जैसे आयकर) और अप्रत्यक्ष करों (जैसे जीएसटी, आयात शुल्क) की दरों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया है। यह निर्णय व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता लाता है और मौजूदा आर्थिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है|
13. स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ/पेंशन फंडों के लिए कर लाभ:स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंडों द्वारा किए गए निवेशों के लिए कर लाभ बढ़ाए गए हैं। यह उपाय इन इकाइयों को अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ेगा और नवाचार और विकास को समर्थन मिलेगा।
14. करदाता सेवाओं में सुधार:सरकार ने एक निश्चित राशि तक बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है, जो करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। इससे उन व्यक्तियों और व्यवसायों को लाभ होगा जिन्होंने समय पर कर जमा किया है लेकिन किन्हीं कारणों से अतिरिक्त बकाया है। इससे करदाताओं की वित्तीय बोझ कम होगा और सरकार के साथ उनके संबंध में सुधार होगा।

इन उपायों का उद्देश्य न केवल कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और करदाता-अनुकूल बनाना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और निवेश की एक स्वस्थ परिस्थिति विकसित हो। ये उपाय आर्थिक नीतियों में स्थिरता और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2024 एक सकारात्मक और भविष्य के लिए उन्मुख बजट है जिसका उद्देश्य पिछले 10 वर्षों के लाभों पर निर्माण करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।